**भारत सरकार**
**श्रम और रोजगार मंत्रालय**
**राज्य सभा**
**तारांकित प्रश्न संख्या- *66**
**गुरूवार, 5 फरवरी, 2026/16 माघ, 1947 (शक)**

## बेरोजगारी दर

***66. श्री रामजी लाल सुमन:**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि देश में बेरोजगारी की दर बहुत अधिक है और युवाओं की रोज़गार-योग्यता बहुत कम है;
(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;
(ग) क्या सरकार, विशेषकर शिक्षित युवाओं में, उच्च बेरोजगारी दर का समाधान करने के लिए कदम उठाने का विचार रखती है;
(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**
**श्रम और रोजगार मंत्री**
**(डॉ मनसुख मांडविया)**

**(क) से (ङ):** एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।
*

**"बेरोजगारी दर" के संबंध में सांसद श्री रामजी लाल सुमन द्वारा दिनांक 05.02.2026 को पूछे गए राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *66 के उत्तर में संदर्भित विवरण**

(क) से (ङ): रोजगार और बेरोजगारी का डाटा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) द्वारा एकत्र किया जाता है। यह सर्वेक्षण सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-18 से किया जा रहा है।

नवीनतम वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्टों के अनुसार, सामान्य स्थिति के आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) वर्ष 2017-18 में 6.0% से घटकर वर्ष 2023-24 में 3.2% हो गई है और इसी अवधि के दौरान 15-29 वर्ष की आयु के युवाओं के लिए अनुमानित यूआर 17.8% से घटकर 10.2% हो गया है।

इसके अतिरिक्त, देश में सामान्य स्थिति के आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए रोजगार को दर्शाने वाला अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) वर्ष 2017-18 में 46.8% से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 58.2% हो गया है और इसी अवधि के दौरान 15-29 वर्ष की आयु के युवाओं के लिए अनुमानित डब्ल्यूपीआर 31.4% से बढ़कर 41.7% हो गया है।

इसके अतिरिक्त, वर्ष 2017-18 और वर्ष 2023-24 के दौरान विभिन्न सामान्य शिक्षा स्तरों के 15-29 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं के लिए सामान्य स्थिति में अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) निम्नानुसार है:

| **बेरोजगारी दर (% में)** | | |
|---|---|---|
| **सामान्य शैक्षिक स्तर** | 2017-18 | 2023-24 |
| साक्षर और प्राथमिक शिक्षा तक | 8.3 | 2.6 |
| पूर्व-माध्यमिक | 13.7 | 4.2 |
| माध्यमिक | 14.4 | 4.9 |
| उच्चतर माध्यमिक | 21.1 | 8.8 |
| माध्यमिक और उससे अधिक | 25.4 | 15.4 |

*स्रोत: पीएलएफएस, एमओएसपीआई*

उपरोक्त आंकड़े दर्शाते हैं कि विभिन्न सामान्य शिक्षा स्तरों के लिए बेरोजगारी दर में भी पिछले कुछ वर्षों में कमी आई है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार जानकारी पीएलएफएस रिपोर्टों में उपलब्ध है, जिसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की वेबसाइट https://www.mospi.gov.in/publications-reports पर देखा जा सकता है।

रोजगार सृजन के साथ-साथ रोजगार क्षमता में सुधार (युवाओं सहित) सरकार की प्राथमिकता है। तदनुसार, सरकार देश में विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रही है। सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes पर देखा जा सकता है।

सरकार कौशल भारत मिशन (एसआईएम) के तहत, देश भर में कौशल विकास केंद्रों/विद्यालयों /महाविद्यालयों/ संस्थानों आदि के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से विभिन्न योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) तथा शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) आदि के तहत कौशल, पुन: कौशल और कौशल संवर्धन प्रशिक्षण का कार्यान्वयन भी कर रही है। एसआईएम का उद्देश्य भारत के युवाओं को उद्योग जगत से संबंधित कौशल प्रदान करके भविष्य के लिए तैयार करना है।

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई**)** ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित 10 नई/उभरती प्रौद्योगिकियों में रोजगार के लिए आईटी कर्मियों की री-स्किलिंग/अप-स्किलिंग के लिए **'**फ्यूचर स्किल्स प्राइम**'** कार्यक्रम शुरू किया है।

सरकार विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हुए, सभी क्षेत्रों में रोज़गार सृजन, रोज़गार क्षमता और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री विकसित भारत रोज़गार योजना नामक रोज़गार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना को कार्यांवित कर रही है। 99,446 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली इस योजना का उद्देश्य 2 वर्षों की अवधि में देश में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगारों के सृजन को प्रोत्साहित करना है।

इसके अलावा, भारत सरकार का श्रम और रोजगार मंत्रालय, राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल चला रहा है, जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म [www.ncs.gov.in] के माध्यम से निजी और सरकारी क्षेत्रों की नौकरियों, ऑनलाइन और ऑफलाइन रोजगार मेलों की जानकारी, नौकरी खोज और मिलान, करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों की जानकारी, कौशल/प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि करियर से संबंधित सेवाएं प्रदान करने के लिए वन-स्टॉप समाधान है।

*****